FROM NEWS PAPER

1. Dainik Bhaskar 14.02.2009

छात्राओं की शिकायत, दो शिक्षिकाएं निलंबित

बलौदाबाजार. कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पदस्थ शिक्षाकर्मी वर्ग-1 श्रीमती चमेली टंडन और शिक्षाकर्मी वर्ग-2 निर्मला वर्मा को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रसन्ना आर ने निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ छात्राओं ने आपत्तिजनक हरकतें करने का आरोप लगाया था। छात्राओं ने आरोप लगाया था कि यहां की शिक्षिकाएं स्नान करती छात्राओं की डिजिटल कैमरे से तस्वीरें लेती हैं। इससे पालक भी विचलित थे। जनपद पंचायत के सीईओ द्वारा जांच में शिकायत सही पाई गई। निलंबन अवधि में दोनों शिक्षाकर्मियों को जनपद पंचायत मैनपुर में संलग्न कर दिया गया है। परीक्षा के ऐन पूर्व छात्राओं को कठोर सजा देने का मामला गरमाया हुआ है। गत 5 फरवरी को शाला की शिक्षिका सुनीता ध्रुव ने शाला की लगभग 16 छात्राओं को 30 से 100 बार तक उठक-बैठक की सजा दी थी।

2. Dainik Bhaskar 08.04.2012

3. DainikBhaskar 18.04.2012

अफगानिस्तान में 150 छात्राओं को दिया जहर

काबुल | अफगानिस्तान में मंगलवार को 150 स्कूली छात्राओं को जहर देकर मारने की कोशिश की गई। बच्चियों की गलती यह थी कि उन्होंने हाई स्कूल जाकर पढ़ने की कोशिश की। उत्तरी ताखर प्रांत के शिक्षा विभाग के प्रवक्ता मोहम्मद नवीजादा के मुताबिक घटना को अंजाम देने वालों का पता नहीं चला है। उन्होंने कहा कि, 'यह सौ फीसदी तय है कि पानी में जहर मिलाया गया था। लेकिन किसकी करतूत है यह फिलहाल तय नहीं है।' घटना में तालिबान का हाथ होने की आशंका है। उसने महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध लगा रखा है। शेष | पेज 6

4. **Dainik Bhaskar 11.04.2007**

लड़की होने का गुनाह

बच्चों की स्थिति पर देश के सबसे बड़े सरकारी सर्वेक्षण ने लड़कियों की दुर्दशा का गंभीर अक्स दिखाया है।

देश में ज्यादातर लड़कियों को अगर विकल्प मिलता तो वे लड़का होना पसंद करतीं। यह निष्कर्ष महिला व बाल विकास विभाग के अब तक के सबसे बड़े राष्ट्रीय सर्वे का है। इससे पता चलता है कि हमारी आधी दुनिया में अब भी कितना अंधेरा व अत्याचार है और सभ्यता व सामाजिक विकास के तमाम दावों का यथार्थ क्या है। हालांकि अत्याचार की खबरों और कन्या के प्रति भेदभाव की बातों से कोई अनभिज्ञ नहीं है, लेकिन ताजा तथ्य बताते हैं कि इन्हें हल्के तौर पर लेने या कम से कम सामाजिक स्तर पर विकसित होने का भ्रम पालने की जरूरत नहीं है।

बाल अत्याचार पर हुए इस सर्वे में कहा गया है कि तिरेपन फीसदी बच्चे यौन दुराचार के शिकार हुए हैं। इस पर शायद कोई न चौंके क्योंकि हाल में उजागर हुए निठारी कांड ने इस बारे में बखूबी आगाह कर दिया है लेकिन लड़कियों के बारे में कई बातें चौंकाती हैं। मसलन, अड़तालीस फीसदी से ज्यादा कन्याएं लड़की होना ही नहीं चाहतीं, राजस्थान में तो यह प्रतिशत 87 तक पहुंच गया, वहीं उत्तरप्रदेश में 85, मध्यप्रदेश में 79 और दिल्ली में 76 फीसदी है। जाहिर है कि इन राज्यों में लड़कियों की स्थिति कहीं ज्यादा बुरी है। पहले तीन राज्यों को सामाजिक रूप से पिछड़ा मान लिया जाए, तो दिल्ली की स्थिति पर अचरज होता है। इससे यही माना जा सकता है कि प्रत्यक्ष पिछड़ेपन के अलावा कथित रूप से विकसित समाज में भी मानसिक पिछड़ापन बरकरार है। विकसित प्रदेशों में कन्या भ्रूणहत्या के आंकड़े भी इसी का संकेत देते हैं।

सर्वे के मुताबिक छियालीस फीसदी लड़कियां घरों में छोटे भाइयों-बहनों को संभालने में बचपन गुजार देती हैं। इसका आंकड़ा केरल जैसे सर्वाधिक शिक्षित राज्य में बेहद ऊंचा 81 प्रतिशत है। इसी तरह 48 फीसदी लड़कियां मानती हैं कि उनके माता-पिता उनसे ज्यादा तरजीह बेटे को देते हैं। इसका मतलब है कि परिवार के भीतर भेदभाव की जबर्दस्त भावना आज भी मौजूद है। बच्चों पर अत्याचार के 83 प्रतिशत मामले घरेलू होते हैं यानी परिवार अत्याचार व अनाचार की सबसे बड़ी इकाई है जिस पर कानून का राज भी ज्यादा नहीं चल पाता। घरेलू हिंसा भी ऐसा ही मामला है। जाहिर है कि ये प्रवृत्तियां सामाजिक जागरूकता, शिक्षा व विकास से ही बदल सकती हैं। लेकिन इनमें क्या कोई कमी है? प्रत्यक्ष तौर पर नहीं, लेकिन सच यह है कि हमें विकास और पिछड़ेपन के मानक बदलने होंगे। इसके अलावा, बड़ों की हस्तक्षेपकारी दुनिया में बच्चों के लिए भी कुछ संस्थाएं, सोच, सहारे और सदाशयता विकसित करने की जरूरत है। यह अभिभावकों के सहयोग का दायरा बढ़ाकर ही किया जा सकता है।

5. **Dainik Bhaskar 08.04.2012**

मुझसे ये बेरुखी क्यों?

देश की आबादी में हम 48.4 फीसदी हैं

भगवान न करे, मुझे दिल की बीमारी हो। 22 फीसदी बेटियों को ही इसका उपचार मिल पाता है। जबकि लड़कों को 70 फीसदी।

दुःख तो इस बात का भी है कि हमें ठीक से खाना नहीं मिलता। तभी तो 18 से कम उम्र की 90 फीसदी बेटियों को एनीमिया है। लड़कों से कहीं ज्यादा।

मुझे देश से कोई शिकायत नहीं है लेकिन फाइटर पायलट नहीं बन सकती। मोर्चे पर नहीं जा सकती। जिसे वे फुल कमीशन कहते हैं।

मेरे लिए कॉलेज जाना बेहद मुश्किल है। 11 फीसदी बेटियों को ही भेजा जाता है वहां तक। जबकि 15 फीसदी लड़कों को उच्च शिक्षा के लिए भेजा जाता है।

...पूरे देश में बेटियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बल्कि कई जगह तो हालात झकझोर देने वाले मिले। ऐसे में बेटी बचाने को अभियान न मानें ये मानवता के लिए जरूरी है।

रिसर्च एंड टैक्स्टः धीरेंद्र राय, उपमिता वाजपेयी
डिजाइनः प्रदीप कुशवाहा

बीते वर्ष एक हजार लड़कों के पीछे केवल 877 लड़कियां पैदा हुईं

जन्म लेने में पिछड़ी द्विवनसिटी की बेटियां

2011 में द्विवनसिटी में लड़कों के मुकाबले 9 हजार लड़कियां कम पैदा हुई। लिंगानुपात में यह अंतर चिंतनीय है। अगर लोगों की सोच नहीं बदली तो स्थिति और बिगड़ जाएगी।

पुनीत कौशिक. दुर्ग

सरकारी आंकड़े बताते हैं कि दुर्ग-भिलाई द्विवनसिटी में लड़कियों की संख्या घट रही है। एजुकेशन हब की पहचान भले ही द्विवनसिटी को मिल गई है, लेकिन बेटियों के प्रति लोगों का रवैया अच्छा नहीं है। पिछले साल (2011 में) द्विवनसिटी में जन्म लेने वाले बच्चों के लिंग अनुपात के आंकड़े चौंकाने वाले है। इससे आंखें खुल जाना चाहिए।

शासन को भेजी गई 2011 के जीवनांक रिपोर्ट के मुताबिक 2011 में द्विवनसिटी में जन्में एक लाख 34 हजार 669 बच्चों का पंजीयन हुआ है। जिसमें 71 हजार 988 लड़के व 62 हजार 681 लड़कियां है। मतलब लड़कों के मुकाबले 9 हजार 307 लड़कियां कम पैदा हुई है। इस तरह द्विवनसिटी में सालभर में पैदा हुए बच्चों का लिंग अनुपात 877 आ रहा है, यानि पिछले साल एक हजार लड़कों का जन्म हुआ तो लड़कियां 877 ही पैदा हुई। द्विवनसिटी के ये आंकड़े स्थिति की गंभीरता को उजागर कर रहा है। इसकी वजह लोगों की बेटियों के प्रति नाकारात्मक सोच और भ्रूण हत्या को माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि भ्रूण हत्या जैसे घृणित कृत्य सबसे ज्यादा अपर क्लास में है।

लोगों की लाइफ स्टाइल भले ही बदल गई है पर बेटियों के प्रति सोच नहीं बदली है। यही वजह है कि लिंगानुपात का गैप बढ़ता जा रहा है। यह चिंतनीय है कि जहां राजनैतिक व प्रशासनिक क्षेत्र में महिलाओं का वर्चस्व है वहां बेटियों को दुनिया में आने से रोकने के लिए भ्रूण हत्या का सहारा लिया जा रहा है। हर क्षेत्र में लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहीं हैं, बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं में लड़कों से आगे निकल रही हैं फिर भी लोगों की सोच नहीं बदल रही है। भ्रूण की जांच व अवैध गर्भपात पर कानून में दंड का प्रावधान है लेकिन मामला कानून के दरवाजे तक पहुंच ही नहीं पाता। ऐसे में भला किसी को कैसे दंड मिल सकता है।

2011 में जन्मे पंजीकृत बच्चे

दुर्ग शहर में

लड़के - 30882

लड़कियां - 29276

योग - 60158

लड़कियां कम - 1606

भिलाई शहर में टाउनशिप सहित

लड़के- 41106

लड़कियां - 33405

योग - 74511

लड़कियां कम- 7701

सक्षम होने के बावजूद समाज की सोच को बदलने में लड़कियां नाकामयाब हैं।

राष्ट्रीयस्तर पर बच्चों का लिंगानुपात 914

भारत की जनगणना में शून्य से 6 साल तक के बच्चों की गणना अलग से की जाती है। आंकड़े अलग से जारी होते है। इन बच्चों की गणना के आंकड़े भी चिंतित करने वाले है। जनगणना 2011 के आंकड़े देखें तो राष्ट्रीयस्तर पर शून्य से 6 साल तक के बच्चों का लिंगानुपात 914 है। जबकि पुरुषों व महिलाओं का लिंगानुपात राष्ट्रीयस्तर पर 942 है।

जेंडर गैप के मामले में चौथा स्थान

समाजशास्त्री डा. एसके श्रीवास्तव कहते हैं कि लड़का और लड़की के जन्म दर के मामले में पूरे देश में स्थिति अच्छी नहीं है। एक रिपोर्ट का हवाला देकर उन्होंने बताया कि लड़कियों के लिए खतरनाक देशों में भारत चौथे नंबर पर है। भारत में भ्रूण हत्या से लेकर महिला उत्पीड़न के मामले चिंताजनक है। शिक्षित वर्ग में अगर पहली संतान लड़की हुई तो दूसरी संतान को जन्म देने से पहले भ्रूण का पता लगाया जाता है और यदि दूसरी संतान कन्या हुई तो उसे दुनिया में आने ही नहीं दिया जाता।

इन बेटियों के माता-पिता से सबक ले समाज

ऐसा भी नहीं है कि बेटियों के प्रति सोच में बदलाव न आया हो, पर ऐसे लोग कम है पर उनकी अच्छे सोच का परिणाम है कि उनकी बेटियां सफलता हासिल कर रहीं है और अपनी पहचान भी कायम की है। दुर्ग की सांसद सरोज पांडेय को हर कदम पर उनके पिता का साथ मिलता है। यह बात सांसद गर्व के साथ स्वीकार करतीं हैं। कलेक्टर रीना बाबा साहेब कंगाले भी कहतीं हैं कि वे आज जिस मुकाम पर है उसके पीछे पिता का भरपूर सहयोग और प्रोत्साहन है। यही वजह है कि वे अपने नाम के साथ पिता का नाम लिखती हैं। जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी प्राची मिश्रा के माता-पिता पुलिस अधिकारी है। प्राची कहतीं हैं कि उनके माता-पिता ने बेटे-बेटियों में कभी फर्क नहीं समझा। जिसके कारण ही वे लगातार सफलता की सीढ़ी चढ़ सकीं हैं। डिप्टी कलेक्टर सौम्या चौरसिया और आदिवासी विकास विभाग की सहायक आयुक्त माया वारियर की भी परवरिश माता-पिता ने बेटे की तरह की। आईएएस अधिकारी सहायक कलेक्टर रानू साहू एक किसान की बेटी है। उनके माता-पिता ने भी उन्हें हर कदम पर प्रोत्साहित किया।

PHOTOGRAPHS

Classroom

Stereo Type Work

Classroom

Sitting arrangement in Classroom

Classroom interaction

महिला प्रसाधन